लोकमत समाचार

शनिवार ८ जनवरी २००५, नागपुर ११

पुनर्वास के लिए विशेष बैंक की स्थापना जरूरी : अग्रवाल

मकरंद गाडगिल >> नई दिल्ली, ७ जनवरी.

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के अध्यक्ष डा. जे. डी. अग्रवाल ने आज यहां प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों के पुनर्वास पर गंभीरता से और तत्परता से ध्यान देने की जरूरत बताई. उन्होंने मांग की कि पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक विशेष बैंक की स्थापना की जानी चाहिए.

'लोस' से खास बातचीत में श्री अग्रवाल ने बताया कि गुजरात के भूकंप के बाद तत्कालिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेजी ने आपदा पीड़ितों के लिए इस तरह के विशेष बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था. इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से इस संबंध में एक पत्र भी आया था. साथ ही तत्संबंधी प्रस्ताव भी पेश किया गया. लेकिन पूर्व की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने किसी तरह की कार्यवाही नहीं की. उनका कहना था कि भारत जैसे विशाल देश में किसी न किसी हिस्से को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है. अत: इन स्थितियों के मद्देनजर इस तरह के बैंकों की सख्त जरूरत है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि दूसरे महायुद्ध की तबाही के बाद ब्रिटेन, जापान, जर्मनी आदि देशों ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक की स्थापना की थी. उसी का आगे चलकर विश्व बैंक में रूपांतर हुआ. इस तरह की बैंक का अस्तित्व हमारे देश में होता तो पुनर्वास कार्यों के लिए कम से कम तीन हजार करोड़ रुपए आसानी से उपलब्ध हो जाते. अपनी योजना के बाबत जानकारी देते हुए उन्होंने आगे कहा कि यह विशेष बैंक पांच सौ करोड़ रुपए कि हिस्सा पूंजी से शुरू की जा सकती हैं. इस प्रारंभिक पूंजी के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वित्तीय संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं एवं आम जनता से प्रत्येक से सौ करोड़ रुपए के हिसाब से रकम आसानी से जुटाई जा सकती है. पांच सौ करोड़ रुपए की हिस्सा पूंजी की बिना पर विशेष बैंक पुनर्वास कार्यों के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशिया विकास बैंक आदि संस्थाओं से तीन से चार प्रतिशत के मामूली ब्याज दर पर तीन हजार करोड़ रुपए का दीर्घावधि ऋण हासिल कर सकता है. पश्चात जो राज्य प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं उन्हें एक या आधा प्रतिशत अधिक ब्याज दर पर पुनर्वास कार्यों के लिए धन मुहैया करा सकता है. इन राज्यों को कर्ज के रूप में आर्थिक मदद देने का फायदा यह होगा कि दी गई रकम योग्य कार्यों पर ही खर्च की जाएगी. इसका भरोसा रहेगा. श्री अग्रवाल का तर्क था कि अभी यह हो रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पुनर्वास कार्यों के लिए रकम दी जाती है